दैनिक जागरण, २९-५-१६
पृ० 12

# कर चोरों के लिए 'टैक्स हैवन' बन सकती है खेती

## संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से की सख्ती की मांग

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** खेती से घटती आय और बढ़ते कर्ज से किसान भले ही आत्महत्या को मजबूर हों लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना कृषि आय एक करोड़ रुपये से अधिक है। देश में ऐसे लोगों की संख्या 100-200 नहीं बल्कि हजारों में है। खास बात यह है कि इनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई तो किसी और पेशे से है लेकिन टैक्स बचाने के मकसद से वे इसे कृषि आय के रूप में दिखा रहे हैं। यही वजह है कि संसदीय समिति ने खेती की आड़ में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि खेती के नाम पर कर चोरी से देश के भीतर 'टैक्स हैवन' बन सकता है।

### वित्त मंत्रालय की खिंचाई

वित्त मामले संबंधी संसद की स्थाई समिति ने बृहस्पतिवार को लोक सभा में पेश अपनी रिपोर्ट में खेती से एक करोड़ रुपये की आय दिखाने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि को गंभीरता से न लेने पर वित्त मंत्रालय की खिंचाई की है। समिति ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि राजस्व विभाग इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे मामलों की अनदेखी से देश में 'टैक्स हैवन' बन जाएंगे। इस तरह के टैक्स हैवन में

- कहा, खेती के नाम पर टैक्स चोरी से बन जाएगा देश में 'टैक्स हैवन'
- खेती से करोड़ों की आय दिखाने वालों की संख्या अचानक बढ़ी




कृषि आय के नाम पर कालाधन जमा हो सकता है। समिति ने वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है।

### विभाग भी अंधेरे में

असल में समिति ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या यह बात सही है कि देश में 2,746 करदाता ऐसे हैं, जिनकी कृषि से आय एक करोड़ रुपये से अधिक है। चौंकाने वाली बात यह है कि आयकर विभाग के पास इसका पूरा ब्यौरा नहीं है। विभाग का कहना है कि आकलन वर्ष 2007-08 से 2015-16 के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक कृषि आय दिखाने वाले करदाताओं की संख्या 2349 है।

### जांच में सच्चाई सामने आई

विभाग का कहना है कि खेती से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय दिखाने वाले कई करदाताओं की आय से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला है कि उनकी यह कमाई कृषि से नहीं थी।

### लघु बचत का ब्याज घटाने पर आपत्ति

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** वित्तीय मामलों की स्थाई संसदीय समिति ने लघु बचत की ब्याज दरों में कटौती होने का मामला उठाया है और कहा है कि सरकार को ब्याज दरों की समीक्षा करते समय वरिष्ठ नागरिकों और पीपीएफ खाताधारकों का ख्याल करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा है कि बैंको की मांग पर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने को ब्याज दरों में कटौती की गई। जबकि बैंकों की जमा राशियों की तुलना में लघु बचत बहुत कम है।

29/5/16
प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट